भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2873
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

वैश्विक क्षमता केंद्र

2873. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और इनमें नियोजित व्यक्तियों की राज्यवार और शहरवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त जीसीसी द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल वार्षिक राजस्व का क्षेत्रवार, वर्षवार और शहरवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में, टियर-2/3 शहरों, जिसमें विशाखापत्तनम, काकीनाडा और विजयनगरम जैसे शहर शामिल हैं, में जीसीसी की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है या सहायता की है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) टियर-2 और टियर-3 शहरों में वर्तमान में कार्यरत जीसीसी की राज्यवार संख्या कितनी है;
(च) क्या सरकार उभरते शहरों और छोटे कस्बों में जीसीसी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किसी नीतिगत समर्थन, अवसंरचना के प्रोत्साहन या विशेष आर्थिक पैकेज पर विचार कर रही है; और
(छ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रोत्साहन, लक्षित भौगोलिक क्षेत्र और कार्यान्वयन समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़ (नैसकॉम) के अनुसार, भारत में 1700 से अधिक जीसीसी संचालित हैं।

पिछले 5 वर्षों में इन जीसीसी द्वारा अर्जित कुल राजस्व 9.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वित्त वर्ष 2019 में 40.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 64.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जीसीसी बुनियादी कार्यों के लिए सहायता केंद्रों से बढ़कर अनुसंधान एवं विकास तथा डिज़ाइन केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं ।

कुल मिलाकर, ये जीसीसी देश में 19 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं।

भारत के जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि टियर II शहरों में जीसीसी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन देने हेतु एक राष्ट्रीय ढाँचा बनाया जाएगा। यह ढाँचा प्रतिभा और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता बढ़ाने, भवन उपनियमों में सुधार करने और उद्योग के साथ सहयोग के तंत्र के लिए उपाय सुझाएगा।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि जैसी कई राज्य सरकारों ने जीसीसी की स्थापना और विस्तार को समर्थन देने के लिए समर्पित नीतियां तैयार की हैं।

*****